

भारत में मृदा क्षरण से निपटना

यह संपादकीय 09/12/2024 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित “[Nourishing our soil](#)” पर आधारित है। इस लेख में भारत की कृषि स्थिरता की बहुत बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें मृदा के बगिडते स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 5% से भी कम मृदा में प्रयाप्त नाइट्रोजन है और केवल 20% में प्रयाप्त कार्बनकि कार्बन है। यूरिया पर केंद्रित वर्तमान उत्तरक सब्सिडी प्रणाली पोषक तत्त्वों के असंतुलन का कारण बनती है, उत्पादकता को कम करती है तथा प्रयावरण क्षरण में योगदान देती है, जिसके लिये तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

प्रलिमिस के लिये:

[मृदा स्वास्थ्य में गरिवट](#), [भारत की कृषि स्थिरता](#), [रासायनिक उत्तरक](#), [अनियमित चारण](#), [हमियल प्रदेश बाढ़- 2023](#), [चार धाम राजमारण](#), [आकर्षक बनस्पति प्रजातियाँ](#), [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#), [प्रंप्राणत कृषि विकास योजना](#), [मनरेगा](#), [भूमि क्षरण तटस्थिता](#), [हैप्पी सीडर](#)

मेन्स के लिये:

भारत में मृदा क्षरण के प्रमुख मुद्दे, भारत में प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के उपाय

[भारत की कृषि स्थिरता मृदा स्वास्थ्य में गरिवट](#) के कारण एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। हाल के आकलन से पता चलता है कि 5% से भी कम भारतीय मृदा में नाइट्रोजन का स्तर अधिक है, जबकि केवल 20% में प्रयाप्त कार्बनकि कार्बन है। वर्तमान उत्तरक सब्सिडी प्रणाली, जो मुख्य रूप से यूरिया पर केंद्रित है, ने असंतुलित पोषक तत्त्वों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिसमें अत्यधिक नाइट्रोजन एवं अप्रयाप्त फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग शामिल है। यह पोषक तत्त्व असंतुलन न केवल कृषि उत्पादकता को कम करता है बल्कि प्रयावरण क्षरण में भी योगदान देता है। इन चुनौतियों का समाधान करने और दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।

भारत में मृदा क्षरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

- वर्तमान स्थिति:** भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस (SAC- 2021) से पता चलता है कि सितं 2018-19 के दौरान भूमि क्षरण की वर्तमान सीमा 97.85 मलियन हेक्टेयर थी, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 29.77% है।
- भौगोलिक वसिताएँ और गंभीरता:** अर्दध-शुष्क और शुष्क उप-आरद्ध क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं तथा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण भूमि क्षरण देखा गई है।
 - अकेले राजस्थान में 21 मलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षरति क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के शुष्क क्षेत्रों में वायु जनति क्षरण है।
 - मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है तथा अब 83.69 मलियन हेक्टेयर भूमि को मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वर्ष 2003-05 के बाद से 1 मलियन हेक्टेयर से अधिक की नविल वृद्धि है।

भारत में मृदा क्षरण के प्रमुख कारण क्या हैं?

- असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ:** [रासायनिक उत्तरक](#), [कीटनाशकों](#) और [एकल फसल उत्पादन](#) के अत्यधिक प्रयोग सहित गहन कृषितिकनीकों पर भारत की नियन्त्रिता के परणामस्वरूप पोषक तत्त्वों की कमी एवं मृदा अमलीकरण हुआ है।
 - उदाहरण के लिये, पंजाब और हरयाणा को हरति क्रांतिकी उच्च उपर वाली फसलों की प्रंप्राण के कारण कार्बनकि कार्बन के स्तर में गरिवट का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत में DDT और HCH जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक वर्तमान में प्रयुक्त कीटनाशकों का 70% से अधिक हस्तित है।
- नियन्त्रित करण (वनों की कटाई) और शहरीकरण:** कृषि, बुनियादी अवसंरचना और शहरी वसिताएँ के लिये तेज़ी से नियन्त्रित करण से मृदा क्षरण में वृद्धि होती है तथा जल धारण क्षमता कम हो जाती है।
 - हाल के आँकड़ों से पता चला है कि भारत के प्राकृतिक वनों में वर्ष 2013 से 2023 तक वृक्षावरण की 95% हानि हुई है।
 - उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट जो 36 वैश्वकि जैवविधिता हॉटस्पॉट में से एक है, में सदाबहार वन क्षेत्र में 5% की कमी देखी गई, जिससे स्थानीय मृदा की उत्तरता प्रभावित हुई।
- अतिरिक्त और असंवहनीय पशुधन प्रबंधन:** [अनियमित चारण](#) से वनस्पति की हानि होती है, जिससे ऊपरी मृदा का क्षरण होता है, वशिष रूप से

राजस्थान और गुजरात जैसे शाषक एवं अरद्ध-शाषक क्षेत्रों में

- भारत में 535 मलियन से अधिक पशुधन हैं जो धारणीय वहन क्षमता से अधिक हैं। पशुधन की संख्या में वृद्धि के कारण चरागाह भूमि पर दबाव बढ़ गया है, जिसके परणामस्वरूप अत्यधिक चारण और वनस्पति आवरण का बनाए रहा है।
 - जल क्षुप्रबंधन और सचिर्ई पद्धतियाँ: अत्यधिक भूजल नष्टिकरण और नमिन स्तरीय सचिर्ई तकनीक, जैसे **गहन सचिर्ई** (Flood Irrigation) के परणामस्वरूप मृदा की लवणता बढ़ती है तथा जलभाव होता है।
 - अत्यधिक सचिर्ई के कारण जल लवणता में वृद्धि हुई है। देश में लगभग 6.74 मलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणता से प्रभावित है।
 - पंजाब में अत्यधिक सचिर्ई के कारण लवणीकरण के कारण लगभग 50% भूमि क्षरति हो गई है, जिसके कारण जलभाव हो गया है और सतह पर नमक/लवण संचयन हो गया है।
 - अनुमान बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष लगभग 10% अतरिक्त क्षेत्र लवणीय हो रहा है और वर्ष 2050 तक लगभग 50% कृषियोग्य भूमि लवण प्रभावित हो जाएगी।
 - औद्योगिक प्रदूषण और खनन गतिविधियाँ: उद्योगों द्वारा भारी धातुओं, रसायनों और प्रदूषकों को निकटवर्ती मृदा परस्थितिकी तंत्र में उत्सर्जित किया जाता है, वशिष्ट रूप से ओडिशा एवं झारखण्ड जैसे खनन-प्रदूषण राज्यों में।
 - कोयला खनन और फ्लाई ऐश डंप से उत्पन्न विषाकृत प्रदूषण ने भूमि के बड़े हस्तिकों को अनुपजाऊ बना दिया है।
 - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉफर संयंतर द्वारा वायु और आस-पास के जल निकायों में ज़हरीले रसायनों के उत्सर्जन के कारण गंभीर मृदा एवं जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
 - जलवायु परविरत्न और चरम मौसम घटनाएँ: जलवायु परविरत्न से प्रेरित घटनाएँ, जैसे अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़, मृदा अपरदन और पोषक तत्त्वों की कमी को बढ़ाती हैं।
 - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2023 में हमियाचल प्रदेश में आई बाढ़ के कारण कृषिक्षेत्रों में मृदा की ऊपरी सतह का भारी क्षय हुआ।**
 - जलवायु परविरत्न के कारण सदी के अंत तक उच्च या बहुत अधिक मृदा अपरदन दर वाले क्षेत्रों की संख्या 35.3% से बढ़कर 40.3% हो जाने की संभावना है।
 - स्थानांतरित कृषिया झाम कृषि और कर्तन एवं दहन प्रथाएँ: नगालैंड और मणपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित खेती/झाम कृषि के कारण मृदा की उरवरता में गरिवट जारी है, क्योंकि इसके तहत कर्तन एवं दहन चक्र कारबनिक पदार्थों को नष्ट कर देती है।
 - पूर्वोत्तर भारत में कुल 4925 वर्ग कमी क्षेत्र को झामगी हॉटस्पॉट के रूप में अभनिरिधारित किया गया है, जिसमें से 62% से अधिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में आता है, जिससे व्यापक मृदा क्षरण एवं जैवविधिता का हरास होता है।
 - अनियमित नरिमाण और बुनियादी अवसंरचना परायेजनाएँ: सड़कों, बांधों और शहरी बस्तियों के लिये बड़े पैमाने पर नरिमाण से ऊपरी मृदा नष्ट हो जाती है तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न बाधित हो जाता है।
 - उदाहरण के लिये, उत्तराखण्ड में **चार धाम राजमार्ग** के नरिमाण के कारण मृदा अस्थरिता और भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं, राजमार्ग के एक भाग पर 300 से अधिक घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
 - आक्रामक प्रजातयाँ: **छोटे छोटे छोटे छोटे** (पंचपूली) जैसी **आक्रामक वनस्पति प्रजातयाँ** का प्रसार पोषक तत्त्वों को कम करके और देशी जैव विधिता को बाधित करके मृदा की उरवरता को कम करता है।
 - हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 22% प्राकृतिक क्षेत्रों में अत्यधिक चतिजनक आक्रामक वनस्पति दर्ज किये गए हैं तथा अनुमान है कि इनमें 66% प्राकृतिक क्षेत्रों को खतरा हो सकता है।

Government Initiatives for Soil Conservation



मृदा संरक्षण से संबंधित भारतीय सरकार की पहल आंशकि रूप से ही प्रभावी क्यों रह जाती है?

- **खंडति नीतिफ्रेमवरकः:** भारत की मृदा प्रबंधन नीतियाँ कई मंत्रालयों और योजनाओं में वर्खिंडति हैं, जिसके कारण समन्वय एवं फोकस की कमी होती है।
 - उदाहरण के लिये, [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#), प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना (सचिवाई) और [मनरेगा](#) (भूमिपुनर्भरण) जैसे कार्यक्रमों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है।
 - यह दृष्टिकोण समग्र मृदा प्रबंधन को रोकता है।
- **अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी:** यद्यपि मृदा स्वास्थ्य कार्ड और [प्रपरागत कृषि विकास योजना \(PKVY\)](#) जैसी योजनाओं का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है, लेकिन ज़मीनी सतर पर इनके कार्यान्वयन में काफी बाधाएँ आती हैं।
 - वर्ष 2022 के आँकड़ों से पता चलता है कि केवल 33% कसिान ही मृदा स्वास्थ्य संबंधी सफिरशिंगों का प्रयोग करते हैं। जबाबदेही व रयिल टाइम फीडबैक की कमी से प्रभाव और कम हो जाता है।
- **क्षेत्रीय वशिष्टिता की उपेक्षा:** अधिकांश मृदा स्वास्थ्य पहल सामान्य हैं और वे राजस्थान में मरुस्थलीकरण या गुजरात में लवणता जैसी क्षेत्र-वशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में वफिल रहती हैं।
 - इस एक ही नीति के कारण मृदा प्रबंधन पहल की प्रभावकारता प्रभावित होती है।
- **अनुसंधान और कार्यान्वयन के बीच कमज़ोर संबंधः** ICAR और IIT जैसे संस्थानों द्वारा भारत में मृदा अनुसंधान के परिणामों को प्रभावी रूप से क्षेत्र-स्तरीय समाधानों में परविरतति नहीं किया जाता है।
 - उदाहरण के लिये, [बायोचार](#) और [माइक्रोबायोल उत्तरक](#) जैसे नवाचारों का व्यावसायिकरण के लिये सरकारी समर्थन की कमी के कारण कम उपयोग किया जाता है। यह वयोग मृदा स्वास्थ्य सुधार पर अनुसंधान एवं विकास के प्रभाव को कम करता है।

भारत में प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना:** जैवकि कृषि, फसल चक्र और कृषि वानकिंग को प्रोत्साहित करने से कार्बनकि पदारथ एवं सूक्ष्मजीव गतिविधियों वृद्धिकरके मृदा के स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता है।
 - प्रपरागत कृषि विकास योजना जैवकि कृषि का समर्थन करती है, लेकिन कसिनों को अधिक प्रशक्षण देकर इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है।
 - मृदा की रयिल टाइम मॉनिटरिंग के लिये PKVY को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ जोड़ने से क्षेत्र-वशिष्ट सफिरशिंगों सुनाशित हो सकती है।

- वाडी प्रणाली को बढ़ावा देना: भारत में पारंपरिक वृक्ष-आधारित कृषि पद्धति वाडी प्रणाली के तहत कृषि, बागवानी और वानकी को एकीकृत किया जा सकता है।
 - यह कृषि वानकी को एक सतत अभ्यास के रूप में बढ़ावा देता है, कृषि को रोककर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जल संरक्षण करता है और जैवविधिता को समृद्ध करता है।
 - यह दृष्टिकोण सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और संधारणीय कृषि को भी समर्थन देता है, जिससे यह प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये एक मूल्यवान उपाय बन जाता है।
- जल प्रबंधन तकनीकों में सुधार: ड्रपि और स्प्रिंकिलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सचिर्वार्षीय विधियों को अपनाने से जल संरक्षण के साथ-साथ जलभराव तथा लवणीकरण में कमी आती है।
 - उदाहरण के लिये, प्रधानमंत्री कृषि सचिर्वार्षीय योजना (PMKSY) का उद्देश्य सचिर्वार्षीय का वसितार करना है, लेकिन जल-मृदा संतुलन को अनुकूलता करने के लिये इसे परिषुद्ध कृषि के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
 - वर्तमान में सूक्ष्म सचिर्वार्षीय कवरेज केवल 19% है, जो इसे बढ़ाने की व्यापक संभावना को दर्शाता है।
- रेत खनन के विरुद्ध वनियमन लागू करना: सख्त नगिरानी और संवन्हनीय रेत खनन नीतियों से नदी तट के अंतर्याकी अपरदन को रोका जा सकता है तथा मृदा पारस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सकती है।
 - नदी तल की नगिरानी के लिये ड्रोन और AI जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, जैसा कि आंध्र प्रदेश रेत खनन वनियमन मॉडल में देखा गया है, अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- बंजर भूमिका पुनः उत्तरता: वनरोपण, चरागाह पुनरुद्धार (जैसे- बन्नी चरागाह पुनरुद्धार) एवं आरद्धभूमिपुनरभरण के माध्यम से भूमि पुनरग्रहण से मृदा अपरदन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जोकि भूमिकरण से निपटने के लिये [संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCCD\)](#) के तहत वर्ष 2030 तक [भूमिकरण तटस्थिता](#) प्राप्त करने की भारत की प्रतिबिंदिता के अनुरूप है।
 - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) जैसे कार्यक्रमों को बेहतर अभिगम के लिये समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों को एकीकृत करना चाहिये।
 - भूमिपुनरुद्धार में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये NAP को मनरेगा के साथ एकीकृत करने से पारस्थितिकी पुनःप्राप्ति और ग्रामीण विकास के दोहरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं।
- संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना: शून्य जुताई, मल्चंगी और कवर फसल जैसी संरक्षण कृषि पद्धतियाँ मृदा की संरचना तथा कार्बन को बढ़ाती हैं।
 - उदाहरण के लिये, लुधियाना, पंजाब स्थित बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (BISA) सक्रिय रूप से शून्य-जुताई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से '[ईपी सीडर](#)' प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से।
 - PMKSY के अंतर्गत इन विधियों को अन्य उच्च उपज वाले क्षेत्रों में वसितारति करने से व्यापक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
- दूषित मृदा के लिये जैव-उपचार अपनाना: सूक्ष्मजीवों और पादपों का उपयोग करके जैव-उपचार से भारी धातुओं एवं औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषित मृदा का शोधन किया जा सकता है।
 - कृषि भूमिका पुनः उपजाऊ बनाने के लिये इस तकनीक का गुजरात के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
 - क्रओसोट प्रभावित मृदा में मलिने के लिये बचे हुए मशरूम कम्पोस्ट में मछली के तेल का प्रयोग दूषित मृदा के लिये जैव-उपचार का एक उदाहरण है।
 - इस संयोजन के परिणामस्वरूप पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) का सबसे प्रभावी अपघटन हुआ।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगता का वसितार: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना को वितरण से आगे बढ़कर इसकी सफिरशिंगों को लागू करने के लिये कसिन शक्ति पर ध्यान केंद्रित जाना चाहिये।
 - SHC डेटा को कसिन सुविधा ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से रयिल टाइम परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
 - इसे स्थानीय [कृषि विजिज्ञान केंद्रों \(KVK\)](#) के साथ एकीकृत करने से कसिनों के लिये ज़मीनी स्तर पर समर्थन सुनिश्चित हो सकता है।
- तटीय मृदा प्रबंधन योजनाएँ बनाना: तटीय क्षेत्रों के लिये व्यापक मृदा प्रबंधन योजनाएँ मैंग्रोव वनरोपण और लवण प्रतिरोधी फसलों के माध्यम से लवणता की अधिक मात्रा को कम कर सकती हैं।
 - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय मशिन जैसी परियोजनाओं को आवास संरक्षण के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।
 - तमलिनाडु के [मैंग्रोव पुनरुद्धार मॉडल](#) को व्यापक प्रभाव के लिये दोहराया जा सकता है।
- अनुसंधान एवं विकास में नविश: जैव-उत्तरकर्तों और कृशल मृदा परीक्षण कटि जैसी मृदा-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने से मृदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।
 - ICAR जैसे संस्थानों को कफियती समाधान खोजने के लिये स्टार्टअप के साथ मलिकर काम करना चाहिये। उदाहरण के लिये, बायोचार उत्पादन को कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत करने से अपशिष्ट कम हो सकता है और मृदा भी समृद्ध हो सकती है।
- शहरी खाद और चक्रीय अरथव्यवस्था को बढ़ावा देना: नगरपालिका खाद सुविधाओं को प्रोत्साहिति करने से शहरी जैविक अपशिष्ट को उच्च गुणवत्ता वाली खाद में परविरत्ति किया जा सकता है, जिससे रासायनिक उत्तरकर्तों पर निर्भरता कम हो सकती है।
 - कर्नाटक कम्पोस्ट विकास नियम, जो प्रतिदिन 250 टन गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण करता है, एक अनुकरणीय मॉडल है।
 - खाद की बकिरी पर GST छूट के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहिति करने से इसे अपनाने में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
- प्राकृतिक खेती की पहल को सुदृढ़ करना: सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (SPNF) मॉडल जैसी प्राकृतिक खेती तकनीकें मृदा की जैवविधिता को बढ़ाने के साथ-साथ बाय कृषि आदान पर निर्भरता को कम करती हैं।
 - SPNF को स्थानीय कृषि विजिज्ञान केंद्रों (KVK) से जोड़ने से कसिनों द्वारा इसे अपनाना तथा बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
- एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन को बढ़ावा देना: जैविक और जैव-उत्तरकर्तों के साथ-साथ रासायनिक उत्तरकर्तों के संतुलित उपयोग से पोषक तत्त्व असंतुलन को दूर किया जा सकता है।
 - पोषक तत्त्व आधारित सबसाडी (NBS) को संशोधित कर इसमें जैव-उत्तरकर्तों को शामिल करना तथा सुदृढ़ीकृत उत्तरकर्तों को बढ़ावा देना,

बेहतर मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चिति कर सकता है।

- NBS सुधारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा के साथ जोड़ने से कसिन-विशिष्ट सफिरशिंग सुनिश्चिति हो सकती है।
- डिजिटल मृदा स्वास्थ्य मानचतिरण का विकास: मृदा स्वास्थ्य मानचतिरण के लिये एक राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस क्षण की प्रवृत्तियों पर नज़र रखने और स्थान-विशिष्ट उपायों की सफिरशिंग करने में मदद कर सकता है।
 - आवधकि मृदा मानचतिरण के लिये ISRO के पृथक्की अवलोकन उपग्रहों का लाभ उठाने से कार्यान्वयन योग्य जानकारी प्राप्त होगी।
 - इस तरह के आँकड़ों को कृषिनीतियों में एकीकृत करने से परशुराध्य मृदा प्रबंधन पद्धतियाँ संभव हो सकती हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटना: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध के साथ-साथ कृषिप्लास्टिक के बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहयि।
 - जैवनमिनीकरणीय विकल्पों और पुनरुत्करण प्रणालयों को बढ़ावा देने से माइक्रोप्लास्टिक मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
 - बायोडिग्रेडेबल कृषि-प्लास्टिक विकासित करने वाले उदयोगों को प्रोत्साहन देने से इस बदलाव को समर्थन मिल सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना: मृदा संरक्षण में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना बेहतर पहुँच और कार्यान्वयन सुनिश्चिति करता है।
 - उदाहरण के लिये, गुजरात का सहभागी वाटरशेड कार्यक्रम एक आदर्श हो सकता है।
 - ऐसे समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडलों को देश भर में विस्तारित करने से स्वामित्व और सफलता दर में वृद्धि हो सकती है।
- जलवायु अनुकूलन को मृदा संरक्षण के साथ एकीकृत करना: बनरोपण जैसी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ संयोजित करने से जलवायु-प्रेरणा क्षण के विद्युद्ध समुत्थानशीलन उत्पन्न किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये, [जलवायु प्रवित्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष \(NAFCC\)](#) परियोजनाओं को वाटरशेड विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करने से संतुलन हो सकता है।
 - राजस्थान जैसे राज्य ऐसी दोहरे उद्देश्य वाली पहल से लाभान्वति हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

एकीकृत, संधारणीय कृषिप्रदृष्टियों, प्रभावी जल प्रबंधन और लक्षित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से मृदा के क्षण को नियंत्रित करना भारत के कृषिभविष्य के लिये आवश्यक है। भारत की कृषिअरथव्यवस्था, जैसे 57% आजीविका के लिये कृषिपर नियंत्रित और **SDG 15 (भूमिपर जीवन)** को प्राप्त करने, दीर्घकालिक कृषिउत्पादकता, खाद्य सुरक्षा एवं प्रयावरणीय स्थरिता सुनिश्चिति करने के लिये मृदा का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।

???????? ????? ????? ?????:

प्रश्न. भारत में मृदा क्षण के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिये और इससे निपटने के लिये वर्तमान सरकारी उपायों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। मृदा स्वास्थ्य को पुनरस्थापित करने और संधारणीय कृषि सुनिश्चिति करने के लिये अतिरिक्त रणनीतियाँ सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

????????????????????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम)' का उद्देश्य है-
2. सचिति कृषियोग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
3. मृदा गुणवत्ता के आधार पर कसियों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना।
4. कृषिभूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

????????????:

प्रश्न. एकीकृत कृषिप्रणाली (आई.एफ.एस.) कसि सीमा तक कृषिउत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (2019)

